Result Mitra Daily Magazine

मौद्रिक नीति समिति

➢ हालिया संदर्भ :

- 4–6 दिसंबर के बीच RBI (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया) की मौलिक नीति समिति (MPC) की बैठक होने वाली है, जिसमें संभावना है कि लगातार 11वीं बार प्रमुख नीति दर यानि Repo Rate (RR) 6.5% पर अपरिवर्तित रखी जाएगी।
- अगर ऐसा होता है तो 22 महीने में RR में कोई बदलाव नहीं होगा।

➢ संभावित घोषणा :

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जुलाई–सितंबर तिमाही में पिछले सात तिमाहियों का निचला स्तर है।
- इस दौरान यह 5.4% से बढ़ा, जबकि अप्रैल–जून 2024 में यह 6.7% एवं जुलाई–सितंबर 2023 में यह 8.1% की रफ्तार से बढ़ा था।
- उपभोक्ता–मूल्य–आधारित मुद्रास्फीति (CPI) सितंबर 2023 में 5.5% था, जो 14 महीनों में बढ़कर अक्टूबर 2024 में 6.21% तक पहुंच गया।
- विकास की धीमी रफ्तार और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संभव है कि RBI RR पर यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में होगी।

➢ RR में कमी :

- MPC ने अपने पिछले बैठक में मौद्रिक नीति को तटस्थ में बदल दिया, जो संकेत देता है कि भविष्य में RR में कमी के लिए स्थितियां अनुकूल है।
- पिछले महीने वित्त मंत्री ने उद्योगों को बढ़ावा देने एवं क्षमता निर्माण के लिए "सस्ती बैंक ब्याज दरों" की वकालत की।
- इससे पूर्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भी RBI से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का आग्रह किया था।

➢ स्थिर RR और उधार दर :

- अगर RBI, RR को 6.5% पर ही स्थिर रखती है तो RR से जुड़ी सभी "बेंचमार्क उधार दरें" (EBLR) नहीं बढ़ेंगी और ग्राहकों के EMI पर कोई नकारात्मक प्रभाव (वृद्धि) नहीं होगा।
- ऋणदाता के पास फंड–आधारित उधार दर से संबंधित ऋणों पर ब्याज दरों को बढ़ाने का विकल्प होगा, जहां मई 2022 से फरवरी 2023 के मध्य RR में 250 BPS की वृद्धि का प्रसारण नहीं हुआ है।

➢ मौद्रिक नीति समिति :

- यह RBI Act, 1934 के तहत स्थापित एक संविधिक है, जो आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा–स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करती है।
- यह मुद्रास्फीति को 4% + –2% को प्राप्त करने के लिए RR का निर्धारण करती है।
- इसमें 6 सदस्य होते हैं, जो सामान्यतः 2 महीने पर अर्थात एक वर्ष में 6 बार मीटिंग करते हैं।
- इन 6 सदस्यों 3 सदस्य RBI तथा 3 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- RBI के तीन सदस्यों में 1 RBI गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित 1 अधिकारी होता है।
- केंद्र सरकार ने हाल ही में MPC के तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की है, जिनमें राम सिंह, नागेश कुमार और सौगत भट्टाचार्य शामिल है।
- MPC की बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य सामान्यत: 4 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहते हैं।